KLG-KS/1N/12.00

(MR. CHAIRMAN in the Chair)

Q. NO. 61

MR. CHAIRMAN: Question Hour. Q. No. 61.

श्री प्रभात झाः सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि देश में क्या महिला जेलों की संख्या कम है? क्या इनकी संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं या किए गए हैं?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति जी, किसी भी राज्य में महिला कैदियों के लिए जेलों की कमी नहीं है, बैरकों की कमी नहीं है, ये पर्याप्त हैं। आज की स्थिति में पूरे देश में कई राज्यों में सिर्फ महिलाओं के लिए स्पेशली, करीब 18 जेलें बनी हुई हैं और बाकी जगहों पर महिला कैदियों के लिए विशेष बैरकें बनी हुई होती हैं। जो महिला कैदी हैं, उनकी संख्या की तुलना में उनके रखने की स्थिति ऐसी है, जैसे कि देश के सभी राज्यों की जेलों में जो महिला कैदियों को रखने की क्षमता है, उनमें 4,748 महिला कैदियों को रखने की क्षमता है, उसके बावजूद वहां पर सिर्फ 2,985 महिला कैदियों को रखा गया है। तो करीब-करीब कहीं पर भी महिला कैदियों को रखने के लिए जेलों की कमी नहीं और न इसे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है।

Q. NO. 61(CONTD.)

श्री प्रभात झाः सभापति महोदय, पुलिस मैनुअल के अनुसार हर जेल में एक मनोचिकित्सक होना चाहिए, परन्तु उत्तर के अनुलग्नक के पृष्ठ संख्या 2 के अनुसार देश की सभी जेलों में मनोचिकित्सक की नियुक्ति की संख्या शून्य बताई गई है। ऐसा आपके उत्तर में ही दिया गया है। तो क्या इस दिशा में सरकार कोई कार्रवाई करेगी?

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति महोदय, जेल का मामला राज्य सरकारें देखती हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा एक मैनुअल दिया गया है कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिसमें सारी बातों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस पर राज्य सरकारों ने पूरा अमल किया है, ऐसा हम नहीं कह सकते। यह राज्य सरकारों का मामला है और कहीं से ऐसी शिकायत नहीं है, लेकिन वहां पर मनोचिकित्सक न होने के बावजूद भी राज्यों के द्वारा हर जगह उनका ट्रीटमेंट कराने की बात कही गई है। आपके द्वारा यह जो प्रश्न पूछा गया है, यह राज्यों का मामला होने के कारण इस पर हम डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

SHRI K.C. RAMAMURTHY: Sir, in the reply, it has been mentioned that the Government has been issuing advisories to State Governments on improving the conditions of women prisoners. There are 1,597 women prisoners, both convicts and under-trials, in various jails in the country, all of whom are with infant babies who were born either during their stay in jails, or

Q. NO. 61(CONTD.)

they had come to jails with kids. The condition of normal prisoners itself is quite bad.

I would like to know from the hon. Minister the specific steps or instructions that the Government has issued for the welfare of these infants and their mothers.

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः सभापति महोदय, जेल में ऐसे बच्चे, जिनकी आयु 6 वर्ष से कम होती है, उनको अपनी माता कैदी के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। ऐसी माता और शिशु के स्वास्थ्य के प्रति जो भी आवश्यक ज़रूरियात हैं, दवाई और खानपान, इसका ध्यान रखा जाता है। इसमें विशेषकर मैं एक बात और जोड़ दूं कि अगर महिला कैदी गर्भवती होती हैं, तो उनकी प्रसूति के समय भी उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है और अगर चाहिए होता है, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ भी किया जाता है। ये दोनों बातें, जो बच्चे वहां जन्म लेते हैं और जो बच्चे 6 वर्ष के नीचे हैं, उन सबकी देखभाल भी अच्छी की जाती है। इस संबंध में आज तक हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन फिर भी ये सारी बातें राज्य सरकारें देखती हैं।

(1ओ/एकेजी-आरएसएस पर जारी)

AKG-RSS/1O/12.05

Q. NO. 61(CONTD.)

श्रीमती कहकशां परवीन : सभापति महोदय, अभी मंत्री जी ने जवाब दिया कि छोटे बच्चों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल में उनकी माँ के साथ रखा जाता है, तो मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जो छोटे बच्चे वहाँ से निकलते हैं, उनके भविष्य के लिए और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति जी, वहाँ जो महिला कैदी होती हैं, उन सभी के लिए NGO, उनके रिश्तेदार या आवश्यकता पड़ने पर वकील, इन सबसे बात करने की पूरी अनुमति दी जाती है। इसके बाद इन बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके भविष्य के लिए अगर वे चाहें, तो 6 वर्ष के बच्चों को अपने पास रख भी सकती हैं या बाहर स्कूल में admission भी दिला सकती हैं। कुछ जगहों पर ऐसा प्रावधान पहले से है। दिल्ली की सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए hostel में भी प्रवेश दिलाया गया है। यहाँ 22 बच्चे hostel में पढ़ते हैं, ऐसा प्रावधान भी किया जाता है। लेकिन जो बच्चे जेलों में रहते हैं, उनके संस्कार अच्छे हों, इसके लिए भी जेल प्रबंधन ने ऐसी माताओं के लिए free hand रखा हुआ है कि वे बच्चे को वहाँ रखें या बाहर रिश्तेदारों के पास रखें। इसलिए किसी बच्चे में अच्छे संस्कार हों, इस सम्बन्ध में सरकार की जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी की पूर्ति में इसके बारे में सोचा जाता है। इस सम्बन्ध में जो जस्टिस

Q. NO. 61(CONTD.)

कृष्णा अय्यर कमिटी बनी थी, उसने भी इसके बारे में कुछ सिफारिशें की थीं। इसके लिए भी सभी स्टेट्स को इस सम्बन्ध में manual भेजा गया है।

श्री राम विचार नेताम : सभापति महोदय, जेलों में जो स्वीकृत पद हैं और जो lock up किया जाता है, वहाँ कैदियों को रखने की जो स्वीकृत क्षमता है, उसके against दोगुने, तिगुने कैदियों को उन जेलों की बैरकों में रखा जाता है, जिसके कारण उनको कई तरह की बीमारियाँ और तमाम तरह की असुविधाएँ होती हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार की विभिन्न मदों से, चाहे modernization की मद हो, चाहे अन्यान्य मदें हों, उन मदों के माध्यम से जब राज्य सरकारों को support किया जाता है, तो यह सुनिश्चित क्यों नहीं किया जाता कि वहाँ पर कैदियों को रखने की जो स्वीकृत क्षमता है, उसके अनुपात में ही कैदियों को रखा जाए? अगर यह स्वीकृत क्षमता से अधिक हो रहा है, तो उसके अनुकूल वहाँ पर स्वीकृति देकर बैरकों की संख्या बढ़ाई जाए और पदों का निर्माण करके पदों की संख्या बढ़ाई जाए। क्या भारत सरकार के माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में कोई ऐसा निर्देश जारी करेंगे और कोई financial support देकर इसे सुनिश्चित कराने की कोशिश करेंगे?

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति जी, पूरे देश में जेलों की जो कुल क्षमता है, वह 3,66,781 है। वहाँ फिलहाल जो capacity से ज्यादा कैदी रखे गए हैं, मैं उस सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि वहाँ 114 परसेंट कैदी रखे गए हैं। आपने सही प्रश्न किया है कि जरूरत के अनुसार बैरकों की संख्या बढ़ानी चाहिए, जेलों की संख्या बढ़ानी चाहिए।

Q. NO. 61(CONTD.)

यह एक सतत प्रक्रिया होती है और सभी राज्य इस पर काम करते हैं। कई जगहों पर नई जेलें बनाई जा रही हैं, नई बैरकें बनाई जा रही हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि मैंने आपसे पुरुष कैदियों के लिए 114 परसेंट की बात कही है, लेकिन महिला कैदियों के मामले में सिर्फ 70 प्रतिशत महिलाएँ ही जेलों में हैं और उनके मामले में जेलों की capacity 30 परसेंट और है। चूँकि यह प्रश्न महिलाओं को लेकर था, इसलिए मैं यह भी बताना चाहता हूँ, लेकिन जेलों में 114 परसेंट पुरुष कैदी हैं, जिनके लिए क्षमता बढ़ाने का प्रयास होता रहता है।

(समाप्त)

(1पी/केजीजी पर आगे)

KGG-SCH/1P/12.10

Q. No. 62

MR. CHAIRMAN: Question No. 62. Questioner not present. Are there any supplementaries?

SHRI K.T.S. TULSI: Sir, the reply given by the hon. Minister to this vital question concerns not only the freedom of speech of the journalists but also the right of the public to be informed. They have given the reply as if the journalists who have been killed are mere statistics, and there is no concern expressed about the trend which is growing. According a world-wide known organisation, Reporters Without Borders, India is amongst the three top-most dangerous countries for journalists. It has been named that we are more dangerous than Pakistan and Afghanistan, according to Reporters Without Borders. To merely say, 'This is a matter which concerns the States because law and order is a State-subject and, therefore, we are not concerned',...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI K.T.S. TULSI: The point is, Sir, so many journalists have been killed. Is there going to be any policy for protection of journalists in their right to report the truth?

AN HON. MEMBER: Sir, the Government should be acting...

Q. NO. 62(CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Please sit down. It is not your question. Let it be answered.

श्री हंसराज गंगाराम अहीर : सभापति जी, हमारे देश में 2014 में पत्रकारों पर हमलों की कुल 114 घटनाएं हुईं, जिनमें केस रजिस्टर किए गए। 2015 में इस तरह के हमलों के 28 मामले दर्ज हुए। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि देश की कुल जनसंख्या को देखते हुए यह संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए जितनी गंभीरता से देश की स्थिति के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में पत्रकारों पर इतने ज्यादा हमले होते हैं। हमारा देश बहुत बड़ी आबादी का देश है, उसको देखते हुए यह संख्या बहुत ज्यादा नहीं लगती है।...(व्यवधान)... यदि इस प्रकार की कोई घटना घटती है, तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर उस पर कार्यवाही करती हैं। वैसे भी कुल मिलाकर यह मामला राज्य सरकारों का ही है। किसी भी राज्य में अगर कोई गुनाह कायम होता है, एफआईआर होती है, तो उसको राज्य सरकारें ही देखती हैं। हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, जिसमें किसी राज्य सरकार ने इस तरह का कोई केस रजिस्टर करने से मना किया हो। इन सारी बातों के लिए Press Council को भी अधिकार दिए हुए हैं। अगर किसी भी स्टेट में किसी पत्रकार पर हमले की कोई शिकायत आती है, तो Press Council ही उस मामले की शिकायत दर्ज करवाती है। इस तरह का कोई केस रजिस्टर करने में अथवा गुनाह कायम करने में किसी भी पुलिस

Q. NO. 62(CONTD.)

स्टेशन में कोई आनाकानी नहीं की जाती है। अभी तक इसके लिए जितने भी आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उसकी फिगर्स आपको दी गई हैं। किसी भी आरोपी को अरेस्ट करने में पुलिस स्टेशन की तरफ से कोई आनाकानी नहीं होती है।

SHRI DEREK O'BRIEN: Sir, the question and the answer, both refer to the word 'journalist' and I suppose it is in the traditional term--'journalist' being a print-journalist or a television journalist. Sir, in today's digital medium, everyone from the civil society, every citizen, can be a journalist because you can broadcast from your mobile phone. Sir, in this digital age, since you can broadcast from your mobile phone, there is a generation of people known as trolls, who broadcast very negative, abusive stuff, murderous threats, or misogynistic stuff, and the kind of editorial which goes out can also have deep communal differences.

My specific question, Sir, is, in this digital age, as I say where every citizen can be a journalist to broadcast this kind of negativity, is the Minister and his Ministry planning to issue an advisory to high constitutional authorities, including the Prime Minister of India, who are following unknown people on the digital medium? And I don't say they have to know everybody; the Prime Minister himself is not sending out any negative messages. But,

Q. NO. 62(CONTD.)

the people who he is following on the digital media are sending out bile and very venomous...

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI DEREK O'BRIEN: So, my question is: Will the Government consider sending out an advisory to high constitutional authorities, to everybody who is in a responsible position, not to follow these unknown trolls who are spreading rape threats, communal threats and misogynistic threats under guise of anonymity?

(Followed by RPM/1Q)

RPM-KLS/1Q/12.15

श्री हंसराज गंगाराम अहीर: माननीय सभापति जी, माननीय सदन ने जो चिन्ता प्रकट की है, उससे कुछ अंश में सहमत होने के लिए सभी सोच सकते हैं, लेकिन देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः वे अपने-अपने तरीके से लिख भी सकते हैं। अगर कोई गलत टिप्पणी की है, तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। हम किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक नहीं लगा सकते हैं। आपने जो बात कही है कि एक पत्रकार, व्यवसायी या कोई प्रोफेशनल है, इन सभी को संविधान में समान अधिकार होने के कारण पत्रकारों को कोई ऐसी विशेष सुरक्षा देने की बात नहीं सोची गई है। बाकी आपने कहा है कि जो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, यह आपका विचार

Q. NO. 62(CONTD.)

हो सकता है, लेकिन सरकार के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उन पर कोई रोक लगाई जाए। हमारे संविधान के मुताबिक हमें ऐसा कोई अधिकार हमें नहीं है।

SHRI DEREK O' BRIEN: Sir, we are not on the question of freedom of expression...(Interruptions)...Freedom of expression is freedom of expression. ...(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: If you are not satisfied, you know the procedure. ...(Interruptions)...

SHRI DEREK O' BRIEN: I request the Minister; I am not fighting with him. ...(Interruptions)... None of us in this House wants the freedom of expression to be quashed. ...(Interruptions)... My question has not been answered, you know that, Sir.

MR. CHAIRMAN: If the question is not answered, you know how to proceed.

SHRI DEREK O'BRIEN: Okay, Sir.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धे: सर, मैं आपके माध्यम यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में, जब से नई सरकार आई, तब से पत्रकारों पर हमलों की संख्या में बहुत घटौती हुई है और यह संख्या बहुत कम हुई है।

श्री सभापति: आप सवाल पूछिए।

Q. NO. 62(CONTD.)

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सर, मैं सदन में यह बताना चाहता हूं कि जब से नई सरकार आई है, तब से पत्रकारों के ऊपर हमलों की संख्या बहुत कम हुई है। यह बात मैं सदन में रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)...Let me ask my question. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no, you ask your question.

डा. विनय पी. सहस्त्रबुद्धेः सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014 में पत्रकारों पर हमलों के 63 मामले दर्ज़ हुए थे, तो क्या वहां असहिष्णुता के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किया है? ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Silence, please. ...(Interruptions)...

श्री हंसराज गंगाराम अहीरः माननीय सभापति जी, सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है उसमें सत्य यही है कि वर्ष 2014 में पत्रकारों के ऊपर हमलों के 63 मामले दर्ज़ होने की बात हमें रिपोर्ट में बताई गई थी, लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक मामला दर्ज़ होने की बात कही गई है। वहां सारे मामले दर्ज़ होते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है, वह सत्य प्रतीत होती है। वैसे ही पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा भी हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं दी जाती है, यानी हमें अवगत नहीं कराया जाता है कि वहां पर पत्रकारों पर कितने हमले हुए हैं। केवल ये दो स्टेट्स हैं, जो हमें पत्रकारों पर हुए हमलों के बारे में नहीं बताती हैं। बाकी सभी स्टेट्स से हमें

Q. NO. 62(CONTD.)

इस बारे में रिपोर्ट्स मिलती हैं। फिर भी मीडियाकर्मियों पर जो हमले होते हैं, यह सारा मामला राज्य सरकारों का होने के कारण हम इस बारे में पूरी डिटेल्स नहीं दे पाएंगे।

श्री सभापतिः ठीक है।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 63

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति जी, मैं मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 'बाल मजदूरी' शब्द की व्याख्या किन-किन तथ्यों के आलोक में की जाती है तथा उनकी उम्र, उनके परिवेश और उन परिवारों की पृष्ठभूमि क्या है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : सभापति जी, मैंने जो उत्तर दिया है, उसमें बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है। वह इसलिए दी है कि इस सरकार के आने के बाद हमने पहली बार एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया है, जिसके अन्तर्गत बाल श्रम से बहुत सी जगह अलग-अलग एस्टाब्लिशमेंट्स में काम कराना, सारी एनजीओज़ और इन सारे मामलों को देखते हुए हम जो प्रोविजन लाए हैं, जो अमेंडमेंट्स किए हैं, वह इसमें एक बहुत बड़ा और आमूल परिवर्तन है। इसमें पहली बार 1 सितम्बर, 2016 से हमने 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को किसी भी कारखाने में एम्प्लॉय करने को पूरी तरह से निषेध किया है।

(1 आर/पीएसवी पर जारी)

SSS-PSV/12.20/1R

श्री बंडारू दत्तात्रेय (क्रमागत): इस एक्ट में 14 से 18 साल के जो किशोर हैं, उनके लिए एक नयी definition देकर उन्हें adolescent कह कर हमने एक्ट में परिवर्तन किया है, अमेंडमेंट किया है। तो वही एक्ट अभी आगे आया है। लेकिन आपका भी जो विषय है, तो हम लोगों ने इस कानून का और सख्ती से पालन करने का प्रोविजन भी किया है। परिवार के बारे में आपने जो कहा, तो परिवार के बारे में भी हम लोगों ने रूल्स

Q. NO. 63(CONTD.)

फ्रेम करके अपने देश की जो परिस्थिति है, उसको देख कर परिवार में खुद के पिता जी के भाई या बहन के परिवार में काम करने का प्रावधान किया है। बाकी यह है कि इसमें भी employee-employer का relation नहीं है। वह भी सीमित है। वह केवल 2 घंटे उनकी सहायता कर सकता है, काम नहीं कर सकता है। यानी इसमें किधर भी employee-employer का relation नहीं है, वह केवल सहायता कर सकता है। हमने इसमें काफी सोच कर किया है कि हमारे ऐसे देश में बहुत से घरों में छोटे-छोटे काम करने वाले हैं और वे काम भी सीखते हैं। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है, उनको school hours में total prohibition है। हमने Right to Education Act को भी इसमें मिलाया है। तो हमने इसमें परिवार के बारे में बहुत कुछ रूल्स में फ्रेम किया है। अगर एक बार उन रूल्स को थोड़ा समझेंगे, तो उसका समाधान मिलेगा।

श्री राम नाथ ठाकुरः सभापति महोदय, बाल मजदूरी को चिन्हित कर उनकी पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

SHRI BANDARU DATTATREYA: I could not follow the question.

...(Interruptions)...

श्री राम नाथ ठाकुरः मैं बाल मजदूरी को चिन्हित कर उनकी पुनर्स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा जानना चाहता हूँ।

Q. NO. 63(CONTD.)

SHRI BANDARU DATTATREYA: I was unable to really follow the question first because...

श्री हरिवंश: आपने तीन वर्षों में कितने बाल मजदूरों को identify किया और कितनों को rehabilitate किया, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य: तीन सालों में कितने बाल मजदूर identified हुए और क्या कार्रवाई की गई? ...(व्यवधान)...

श्री बंडारू दत्तात्रेय: उसका आंसर मैंने दिया है। इसमें मैंने State-wise information भी दी है। अभी number of working children in 2001 census ...(व्यवधान)...

श्री राम नाथ ठाकुर: सभापति महोदय...(व्यवधान)...

श्री सभापति: एक मिनट। आप जवाब सुन लीजिए।

श्री बंडारू दत्तात्रेय: मैंने एक्ट में जो प्रावधान किये थे, उसमें rehabilitation fund का भी किया गया था। अभी तीन साल के अन्दर का जो data हमारे पास है, उसके अनुसार 2013-14 में 64,050, 2014-15 में 1,16,000 और 2015-16 में 59,076 किया गया, because rehabilitation is one of the major points. For rehabilitation, a separate fund has been provided. In rehabilitation, Sir, for the first time the employers' contribution and, after rescuing the children, the State Government should contribute Rs. 15,000 towards rehabilitation fund. So, ultimately, all these funds, employers' contribution and also State

Q. NO. 63(CONTD.)

Government's contribution, will go into the bank account of the rescued children. And with regard to enforcement also, I have already given.

(Contd. by USY/1S)

USY-VNK/1S/12.25

SHRI BANDARU DATTATREYA (CONTD.): So far as enforcement is concerned, हमने जवाब में 2014-15 और 2015-16 में हुए inspections के बारे में दिया है। हमें दो चीजों से दिक्कत होती है। पहला तो यह है कि स्टेट गवर्नमेंट से information मिलने में हमें बहुत दिक्कत होती है। मैंने तो आपको बिहार का समाचार बताऊंगा। बिहार ही नहीं, बल्कि बहुत से राज्यों की यही हालत है। हमारे पास केवल 13 राज्यों का information आया है, बाकी राज्यों की information नहीं है। The subject matter of 'labour' falls under the Concurrent List. Hence, it should be enforced by the appropriate Government.

DR. NARENDRA JADHAV: Sir, in every eleven children, one child is engaged in child labour. According to the Census 2011, there were about 1,13,00,000 child labour. Then, 62.8 per cent of the adolescents, aged between 15 and 17, are engaged in hazardous works. Against this background, the numbers provided by the hon. Minister clearly show that the inspection rate is abysmally low. The conviction rate is also very poor.

Q. NO. 63(CONTD.)

And, it is further falling. The question again is, why? Does that not mean ineffective implementation of the new Act, which has been passed?

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, as I mentioned, the enforcement is very stringent under the new Act. We have, now, made it a cognizable offence. If I compare the old Act and the new Act, earlier the minimum penalty was Rs. 10,000, which could extend up to Rs. 20,000. Now, the maximum penalty has been increased up to Rs. 50,000. We have also increased the imprisonment in case of a repeated offence. Earlier, for the first time offence, the imprisonment term was three months. Now, we have enhanced it to six months. Earlier the maximum imprisonment was one year. Now, the maximum imprisonment has been increased to two years. That is we have doubled the punishment. Secondly, the employment of adolescents, aged between 14 to 18, is totally banned in hazardous activities. We have also provided a new list of scheduled employment activities. So, the definition of 'hazardous activities' has been changed. The definition of 'adolescents' has also been provided. Thus, the engagement of adolescents in hazardous activities is totally banned.

Q. NO. 63(CONTD.)

श्री अमर शंकर साबले : सभापति महोदय, अभी जिन बच्चों की बात चल रही है, वह तो चलते-फिरते बच्चों की बात चल रही है। महोदय, जो दूध-पीता बच्चा होता है, वह हंसता है, रोता है, लेकिन रास्ते पर भीख मांगने वाली जो औरतें होती हैं, उनके पास जो बच्चा होता है, वह कभी रोता नहीं है, क्योंकि उसको नशे की दवा दी जाती है ताकि लोगों के मन में दया उत्पन्न हो। उस नशे की दवा का उस बच्चे के शरीर और मस्तिष्क पर परिणाम होता है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में केन्द्र सरकार की क्या सोच है?

श्री बंडारू दत्तात्रेय : सर, हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट है, लेकिन the Women and Child Welfare Department is a separate one.

(Contd. by 1t – PK)

PK-NKR/1T/12.30

SHRI BANDARU DATTATREYA (CONTD.): But, we have a provision according to which if such children are there in rehabilitation centres, then, with the help of the National Rural Health Mission, we are handling their problem.

SHRI K.K. RAGESH: Mr. Chairman, Sir, many reports reveal the fact that the children who are engaged in child labour are, basically, from socially and educationally backward sections. Even after 15 years of our Constitutional

Q. NO. 63(CONTD.)

Amendment that made the Right to Education as a fundamental right, around 80 lakh children are still out of school. Majority of those children who are out of school are from socially and educationally backward sections. Sir, my question is, rather than imposing certain penal provisions to curb child labour, whether the Government is aware of or taking care of the aspect of social and educational backwardness also so as to curb the child labour. That is my question, Sir. Thank you.

SHRI BANDARU DATTATREYA: Sir, I agree with the hon. Member that the main reason for child labour is poverty and illiteracy. Because of poverty and illiteracy, as the hon. Member has already mentioned, the number of children who are out of school is also increasing. What I am saying is that in the new Amendment Act, we have proposed to give powers to the District Magistrate and the District Magistrate, in turn, can delegate his powers to subordinates. For them also, we have made a provision in the rules that if a teacher, or, the school management has any information about such children who were earlier coming to schools but now they are unable to come, even they can, with the help of the District Magistrate, go ahead with the process which has been put forth. (Ends)

Q. No. 64

MR. CHAIRMAN: Question No. 64. Questioner is not present. Are there any supplementaries?

SHRI PARTAP SINGH BAJWA: Sir, the Government's focus on Make In India has led to a great deal of neglect towards certain industries that could have otherwise flourished. For example, a place like Jalandhar was a hub for sports goods. In 1992, the FIFA World Cup was played with mostly Jalandhar-manufactured footballs, but, today, the Chinese products are dominating the markets. As per the report of the UNESCO, Sir, now, more than 4.7 crores of secondary and higher secondary students would be using that thing. Also, Sir, there will be a large pool of unskilled workers in the economy in the coming years. But out of the 25 sectors that are there in 'Made In India' website, 22 are heavy-industry-focussed and which require specialised technology and skilled workers. Sir, my question is: What steps has the Minister taken about the unskilled workers who are left out in the process of too much focus on the Make In India Programme?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I, first of all, refuse to believe that the focus given through Make In India has resulted in the sports industry to suffer. As the hon. Member rightly points out that there could be cheaper

Q. NO. 64(CONTD.)

imports coming in, as a result of which, not just sports but many other sectors may also be facing a challenging situation. As regards the list of 25 focussed sectors under Make In India, I would like to point out that leather is also one of them. In that, definitely, the focus is that the people who are semi-skilled or unskilled are also trained to get in. So, the focus largely being on heavy industry, resulting in large-scale unemployment among unskilled workers is, probably, too tenuous an argument to face.

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, as per the assessment recently made by the All India Manufacturers' Association, country's manufacturing sector has suffered a lot due to demonetisation. About 35 per cent of the workers engaged in the sector have been rendered jobless.

(Contd. by PB/1U)

PB-DS/1U/12.35

SHRI AHAMED HASSAN (CONTD.): Sir, my question is: What steps have been initiated by the Government for rehabilitation and compensation of the workers who lost their jobs in manufacturing sector due to demonetization?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I have no reports whatsoever about people who have lost their jobs, particularly, as being highlighted by

Q. NO. 64(CONTD.)

the Member and thereafter to talk about rehabilitation. ...(Interruptions)... So, I am sorry; I am unable to respond to a question which comes out of, I am not sure, what kind of data. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Shri Digvijaya Singh. ...(Interruptions)...

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, the jewellery sector people who work outside West Bengal are coming back in lot; and they are jobless. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: If you are not satisfied with the answer, please take it up. Shri Digvijaya Singh.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I would like to inform the hon. Minister that the impact of demonetization on the manufacturing sector, as reflected in the India Manufacturing Purchasing Managers' Index, PMI, is such that it fell to 49.6 in December from 52.3 in November. Also, Sir, All India Manufacturers' Organization, AIMO, has given a report which, unfortunately, the Minister of Finance as well as other Ministers did not respond to. The job cut has been almost 30-35 per cent and the revenue loss has been almost 50-55 per cent. Would the hon. Minister please tell us what has been the real impact of demonetization in the manufacturing sector?

Q. NO. 64(CONTD.)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, with due respect, I am not sure, where the data comes from. I have a data ... ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: I have mentioned it.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Let me finish, Sir. Let me finish. The hon. Member has asked a question.

श्री सभापति : आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान)... सुन लीजिए। Please proceed.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, the PMI reference that the hon. Member has made initially -- and after that he spoke about the AIMO – jumped, from wherever it was, to 50.4 in January, 2017. So, if that has happened post-demonetization about which the hon. Member is referring to, ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: It is not correct.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am referring to PMI. You referred to PMI too. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... Please let the reply be completed.

Q. NO. 64(CONTD.)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: So, it is the PMI information and the data that I am giving for January, and if you are still talking about demonetization, let me then ask the Member, with due respects, ...

MR. CHAIRMAN: You are answering a question or asking a question!

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I am answering a question with a question because the data which has been given is also here from reference to PMI. ...(Interruptions)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, I will request the Minister to reply to me formally.

MR. CHAIRMAN: Fair enough. Question No. 65.

(Ends)

Q.NO. 65

MR. CHAIRMAN: Shri Neeraj Shekhar, absent. Let the question be answered. Supplementaries. Yes, Mr. Rapolu.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Respected Chairman, the reasons for Retail Selling Price of petrol and diesel not undergoing a similar decrease despite the sliding of prices of petroleum product in international market are included at 'd' – the depreciation of Indian Rupee viz-a-viz US dollar -- of answer to parts (b)&(c) of the question. The reply also indicated the State Government's VAT and other local levies, whereas, the real burden is of excise duty which is gradually increasing at the Union Government level. Why can't the Union Government think of decreasing the excise duty so that it can give some relief to the petrol and diesel users?

COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE: Sir, in fact, from the price in 2013 to the price today, the petrol is actually cheaper. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Where is the Minister? ...(Interruptions)...

COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE: In July-August of 2014, the price was Rs. 73.60, whereas, on January 16, 2017, it is Rs. 71. So, it is lesser. It is the prerogative of the Central Government to provide it for the whole country. ...(Interruptions).. (Followed by 1w/SKC)

SKC-MCM/1W/12.40

Q.NO. 65 (CONTD.)

MR. CHAIRMAN: Just a minute. Please, listen to the reply.

COL. RAJYAVARDHAN SINGH RATHORE: To provide for the whole country, the Central Government collects revenue and this revenue, if the hon. Member were to see the amount spent in 2013 on the public schemes, on infrastructure, on education, is far higher now. So, we are using that money to provide for the country. ...(Interruptions)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: They are not increasing. These are all, in fact, decreasing. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Any other question? ...(Interruptions)...

SHRI MADHUSUDAN MISTRY: Sir, where is the Minister of the concerned Department?

MR. CHAIRMAN: We have intimation that the hon. Minister would be answering on behalf of the Minister. That is as per practice. Now, Question No. 66.

(Ends)

Q. No. 66

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, the rates in the present merchandise export incentive scheme are quite meagre. Some incentives have been either withdrawn or reduced drastically. What steps have been taken by the Government to boost exports and reduce the cost of import?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, there are various schemes. In fact, the Interest Subvention Scheme that has been very successful, which was introduced in late 2015, has proven to be a blessing to the exporters because that has been effectively run through the banks and we have been making sure that it is refilled every now and then without any disruption in serving the exporters. Other than that, of course, you have the scrips being given, which the exporters can effectively use even in repayments. Based on the export performance, the scrips which are given can be used in paying other dues or duties which they owe to the Government. So, this is being continuously monitored. Because performance of exporters is important, not just for the service sector, which is doing fairly well, but also for the merchandise goods, the existing schemes, both incentive-based and also the Interest Subvention Scheme, are effectively helping exporters and we are in constant touch with them to help them further.

Q.NO. 66(CONTD.)

SHRI T.G. VENKATESH: Sir, export incentives would be helpful only temporarily. This problem needs to be solved permanently. A permanent solution could only be reducing the import cost. Let me give you the example of one product, glycerine. The glycerine-processing industry would totally depend on imports. So, the costs and duties on raw and crude glycerine are more while the duty on import of finished products is less. So, the Indian industry would be suffering. The processing industry is almost closing because while there is an increase in the duty on raw material, the duty on finished products has been reduced. We would find this similarity in some other products as well. To cite another example, China gives incentive for power generation. Every industry depends on electrical power. So, the cost of power should be made cheaper. When the cost of power is made cheaper, you need not give incentive for export. Automatically, the finished product would become cheaper and you could export it. This point needs to be considered. Through GST, you plan to simplify Sales Tax in all the States. A uniform GST would be collected in all the States. Similarly, the rates of power must be made uniform. The cost of power in the North-East is just Rs. 2 per unit. There are no processing units in the North-East.

Q.NO. 66(CONTD.)

In the South, there are more such units but the cost of power is more there; it is Rs. 6 or Rs. 7 per unit. If you compare the rates with China, the cost of power is three times more in India. These things need to be taken into account. Probably the Department of Commerce and Industry and other industries must sit together and work things out. Like the GST, a uniform cost of power per unit may be implemented and it should be competitive world-wide. Only then import costs would become cheaper and exports would improve. Giving export incentives is a temporary measure. It would not provide for a permanent solution.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, quite a few points, which the hon. Member has raised, are very relevant in the discourse when we are talking about export and export-related policies. As regards the finding of a permanent solution -- permanent is a long-term solution I suppose -- we are definitely looking at newer markets, newer areas, where the exports can be promoted. So, not just looking at incentives, not just giving scrips, we are also strategizing on how to reach out to newer markets. So, I take the point on the long-term solutions which we need to provide.

(CONTD. BY HK/1X)

HK-SC/1X/12.45

Q.NO. 66(CONTD.)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN (CONTD.): The second aspect that he was talking about is about the inverted duty structure related issues where the end-product is cheaper and raw materials are more expensive. There is a continuous dialogue with the industry and with the Finance Ministry and every Budget since 2015-16 is addressing this issue of inverted duty structure. If the hon. Member is referring to a particular sector where this issue persists, I would request the hon. Member to also contact both the Commerce Ministry and the Finance Ministry so that that specific issue of inverted duty structure can be addressed. As regards the power or other costs, where countries like China do a lot of subsidy-related matters, I agree that logistics cost in India will have to be improved for which we are constantly working with the Shipping, Roadways and other Ministries so that the logistics cost for our exporters is brought down. On power, of course, of the various reforms which are being carried forward, I hope, in the due course of time, we will be able to cut down on the logistics cost for our exporters. The final point that he spoke about is on the North-East. North-East related benefits are provided to those States. Industrialization has to

Q.NO. 66(CONTD.)

reach the North-East for which we are constantly endeavouring. Of course, we have extended the NEIIP, which saw a hiatus in between because of lack of funds. But we are constantly looking at not just the North-East but overall parity in terms of incentives and also productive environment for investment.

श्री अजय संचेती : सभापति महोदय, Demonetization के बाद neighbouring countries से जो बॉर्डर से smuggle होकर कई चीज़ें हमारे देश में आ जाती थीं, वे practically बंद हो गयी हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पिछले दो-तीन महीनों में demonetization के बाद हमारा export बढ़ा है, especially with the neighbouring countries.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: I don't have the data immediately, but I will certainly try to get it for the neighbouring country related trade post November 8. I will try to get it and send it to the hon. Member.

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Hon. Chairman, Sir, Minister Madam said that she would find out which are all the sectors adversely affected by inverted duty structure. In fact, the FICCI in its Report 2016 has mentioned six sectors which are adversely affected by the inverted duty structure, that is, rubber, textiles, electrical, electronics, capital goods and cement. These are all the sectors which are adversely affected by the inverted duty

Q.NO. 66(CONTD.)

structure. Because of the inverted duty structure and also the problem of logistics, these Indian manufacturing merchandise exports have adversely affected. I would like to find out from the hon. Minister whether the Government has initiated any steps to address the logistic problem and the problem of inverted duty structure.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Of course, yes, Sir. Part of my answer for the earlier question was also on the question of how Commerce and Finance Ministries together are addressing every such request or memorandum which reaches us on industry-specific inverted duty structure related issues.

(Contd. by KSK/1Y)

KSK/GS/12.50/1Y

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN (CONTD.): I quite received the comment of those six sectors which the FICCI's report has highlighted. It has highlighted the inverted duty structure issue. The Minister of Finance is fairly seized with the matter. As regards the issue of sectors which are affected, as I said, we do not have, at the moment, industry-specific demonetization-related adverse impact reports with us.

Q.NO. 66(CONTD.)

SHRI MAHESH PODDAR: Sir, we are exporting the steel and value-added engineering goods and these exporters are importing duty-free steel items as their raw material. Now, at the same time, we do also export a lot of steel items to various countries at international price. May I know from the hon. Minister if they can formulate a policy whereby the domestic users of steel for exports can get the steel at international price instead of importing?

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Presently, people, who import the raw materials against advanced licences, do get it duty-free for export purposes, but the specific question as to whether there will be a comprehensive new policy on this, there is nothing at all for me to say at this stage.

(Ends)

Q.No.67

MR. CHAIRMAN: Question No. 67. Questioner not present. Let the answer be laid. Are there any supplementaries?

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, I have a supplementary question.

MR. CHAIRMAN: Mr. Rapolu, you seem to be asking all the supplementaries because the benches are empty. The Members are, obviously, not interested in Question Hour.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, those who are here, please don't castigate us.

MR. CHAIRMAN: I am referring to the absentees.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, with the public sector enterprises, we used to have very good capacity of capital goods, and until and unless we have the sufficient base of the capital goods, we cannot ensure development of the manufacturing sector and the growth in the industrial production. Based on this, your 'Make in India', 'Start-up India' and 'Skill India', put together, could not cater to the needs of the capital goods in enterprises. You have envisaged a policy to increase the growth in capital goods sector from 12 per cent to 25 per cent by 2025. Are you going to co-ordinate with these three things so that you could have the sound footing of

Q.NO. 67(CONTD.)

the capital goods manufacturing sector and we will have a sound industrial foundation?

श्री अनंत गीतेः सभापति जी, सबसे पहले मैं सदन को यह जानकारी देना चाहूंगा कि इसके पहले कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए कोई नीति नहीं थी। हमने पहली बार कैपिटल गुड्स सेक्टर के लिए नीति बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है। ...(व्यवधान)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: We want to know about the heavy industries and heavy industries are capital goods industries.

श्री अनंत गीतेः पहली बार यह पॉलिसी बनी है। इस पॉलिसी के तहत कैपिटल गुड्स सेक्टर से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, चाहे मशीन टूल्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो। ये जो सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें अधिकतर छोटे और मध्यम प्रकार के उद्योग हैं। इस नीति के तहत हम चाहते हैं कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए हमने यह लक्ष्य तय किया है कि अब तक 2 लाख 30 हजार करोड़ का टर्नओवर इस कैपिटल गुड्स सेक्टर में अब तक हुआ करता था। हम चाहते हैं कि इस नीति के तहत इसको 7 लाख 50 हजार करोड़ तक वर्ष 2025 तक बढ़ाएं। जिस प्रकार से हम इस उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसी प्रकार से इस उद्योग के माध्यम से अब तक 14 लाख मजदूरों को रोजगार इस कैपिटल गुड्स सेक्टर से मिल रहा है और

Q.NO. 67(CONTD.)

हमारा यह प्रयास है कि 2025 तक इस 14 लाख की संख्या को बढ़ाकर 50 लाख तक मजदूरों का रोजगार बढ़े। इस पॉलिसी के तहत हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट जॉब्स होते हैं, जिससे आज 70 लाख लोगों को इनडायरेक्ट जॉब्स मिल रहे हैं, उसको बढ़ाकर हम पांच करोड़ जॉब्स क्रिएट करें। हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं और इसी के लिए हम एक पायलट स्कीम चला रहे हैं। हम इस पायलट स्कीम के तहत लगभग 930 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इसमें 581 करोड़ रुपये भारत सरकार की ओर से है और बाकी धनराशि में उद्योग जगत का कंट्रीब्यूशन है। हम जो पायलट स्कीम चला रहे हैं, इस स्कीम को हम आगे और expand करना चाहते हैं, एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जो प्रश्न यहां पर पूछा गया, मैं उसी का जवाब यहां पर देना चाहूंगा।

(HMS/1Z पर जारी)

HMS-GSP/1Z/12.55

श्री अनंत गीते (क्रमागत) : इस स्कीम के तहत हम एक तो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं और इस के साथ-साथ हम ने एक Technology Aquisition Fund create किया है क्योंकि आज विश्व में सारे manufacturing sector में विश्व स्तर पर competition बढ़ा है और इस competition में हमारी इंडस्ट्री टिकी रहे, हमें नयी-नयी टैक्नोलॉजीज़ को अपनाने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने Technology Acquisition Fund गठित किया है जिस के माध्यम से हम टैक्नोलॉजी को यहां ला सकते हैं, खरीद सकते हैं।

Q.NO. 67(CONTD.)

हमने उस पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम इस स्कीम के तहत Centre for Excellence, अलग-अलग क्षेत्रों में नए-नए सेंटर्स खोलने जा रहे हैं, Machine Tool Parks खोलने जा रहे हैं, हम ने कर्णाटक के टुमकूर में ऑलरेडी Machine Tool Park शुरू किया है। इस प्रकार से "मेक इन इंडिया" का जो नारा प्रधान मंत्री जी ने दिया है, उसे सफल बनाने के लिए हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

श्री अजय संचेती : सर, कैपिटल गुड्स मैनुफैक्चर करने वाले भारत सरकार के कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद हैं और भारत सरकार, उन्हें revive करने या उन्हें dispose करने की क्या योजना बना रही है?

श्री अनंत गीते : सर, भारत सरकार के पब्लिक गुड्स सेक्टर में सब से बड़ा पीएसयू बीएचईएल है और बीएचईएल सही दिशा में चल रही है। वह कुछ समय के लिए घाटे में थी, लेकिन इस साल वह फिर मुनाफे में आयी है। कुछ पीएसयूज जो कई सालों से, 2005-2007 से बीमार हैं, जो बंद पड़े हुए हैं और भविष्य में उनके शुरू होने की संभावना नहीं है, वैसे इस प्रश्न से माननीय सदस्य का प्रश्न सीधे जुड़ा नहीं है, लेकिन जो सीपीएसयूज सालों से बंद हैं और जो भविष्य में भी नहीं चल सकते, उन्हें बंद करने का सरकार ने निर्णय किया है। उस दिशा में हमने सही कदम उठाए हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स सेक्टर में, जो निजी क्षेत्र के लोग हैं - माननीय सभापति जी ये अधिकतर निजी क्षेत्र के हैं और वे एसएमईज हैं, जोकि संगठित होकर अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें सरकार की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। (समाप्त)

Q.NO. 68

MR. CHAIRMAN: Q. No. 68. Questioner not present. Let the answer be given. No supplementaries.

(Ends)

Q. No. 69.

MR. CHAIRMAN: Q. No. 69. Questioner not present. Let the answer be given. No supplementaries.

(Ends)

Q. No. 70

MR. CHAIRMAN: Q. No. 70. Questioner not present. ...(Interruptions)... आपने जवाब दे दिया? ...(Interruptions)... Let the answer be given first. Yes, Mr. Yechury.

SHRI SITARAM YECHURY: Sir, this is a very important question and I am very disappointed with the answer that has been furnished by the Government. The question relates to the job losses post-demonetization. The statistics given are from the ILO. It is also clearly written that they have not made any assessment of demonetization. Sir, I do not see the relevance of quoting that figure. You have the figures of Labour Bureau. The Labour Bureau figures were released three days ago, and, about the eight core industries, they have said that there has been a job loss, and 55,000 jobs were lost. These were the eight core industries in which last year you created 1.35 lakh crore of jobs. If in a span of three months, 55,000 jobs, as recorded, is the loss in these core industries, you can imagine the plight in the informal sector, which provides 80 per cent of employment in our country. It contributes 45 per cent of the GDP. This sector has been worst hit due to demonetization. None of that information is here. The question which was asked and the answer which has been given are completely

Q.NO. 70(CONTD.)

unrelated. Why are we talking about the ILO Report on a macro-basis, which also shows that there is a decline in the employment? This is an irrelevant answer. ...(Interruptions)...

SHRI KIREN RIJIJU: What is the question?

SHRI SITARAM YECHURY: The question is: what is the impact on job loss post-demonetization on formal and informal sectors?

(followed by SK-2A)

SK/2A/1.00

SHRI BANDARU DATTATREYA: Actually, there is no proper impact survey ..(Interruptions)..

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over. ..(Interruptions).. I am sorry. What can I do? ..(Interruptions).. Now, the Statement by Minister correcting answer to question, Shri Rijiju.

(Ends)